

**Newspaper Clips**  
**December 12, 2014**

## **IIT Roorkee takes charge of 5 villages under ‘Unnat Bharat Abhiyan’**

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/IIT-Roorkee-takes-charge-of-5-villages-under-Unnat-Bharat-Abhiyan/articleshow/45481014.cms>

Dehradun: In five villages, the Indian Institute of Technology (IIT) Roorkee will spearhead the Union government's 'UnnatBharatAbhiyan', which aims to provide technological resources to rural areas.

Launched by the ministry of human resource development (MHRD), the scheme will be implemented in 132 villages with help from 16 reputed educational institutes. These institutes mostly include IITs and NITs.

According to IIT Roorkee officials, work has already begun in Bhangedi, Telliwala, Chharba, Khanjarpur and Kalsi villages. In a written reply during a Parliament session on December 10, HRD minister SmritiIrani said the scheme had twin objectives of building institutional capacity to educational institutes in terms of research and providing rural India with professional resources.

"The main aim of the 'Unnat Bharat Abhiyan' is to give a tech-boost at the grassroot level to these villages. Work has already been started by IIT Roorkee. Teams have been set up to visit villages and identify their problems. Further, we will aim to find financially-viable schemes and prepare a roadmap for holistic rural development" said a senior professor at IIT Roorkee.

Under the scheme, technologies for rural development are likely to focus on supply of portable water, sanitation, renewable energy, low cost housing and organic farming. Launched on November 11, the programme is being coordinated and steered by IIT Delhi.

**Economic Times ND 12/12/2014 P-15**

## ■ Consortium of Seven IITs Preparing Ganga Plan



**NEW DELHI** A consortium of seven IITs is preparing the Ganga Basin Management Plan and the first version of the project is scheduled to

be submitted by it soon, Lok Sabha was informed on Thursday. Union Minister for Water Resources and Ganga Rejuvenation Uma Bharti said an interim report along with 36 thematic reports have been submitted so far by the consortium of IITs. Bharti said during Question Hour that a number of countries have shown interest in participating in Ganga rejuvenation.

## Financial Express ND 12/12/2014 P-2

### Seven IITs preparing Ganga basin management plan

A consortium of seven IITs is preparing the Ganga basin management plan and the first version of the project is scheduled to be submitted by it soon, the Lok Sabha was informed on Thursday. Union minister for water resources and Ganga rejuvenation Uma Bharti said an interim report along with 36 thematic reports have been submitted so far by the consortium of IITs. Bharti said during Question Hour that a number of countries have shown interest in participating in Ganga rejuvenation. Collaboration with Japan International Cooperation Agency is under consideration in addition to the existing project with JICA assistance of ₹496.9 crore, she said.

## National Duniya ND 12/12/2014 P-11

# सात आईआईटी तैयार कर रहे गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना

नई दिल्ली (एजेसी)। सात आईआईटी का संघ गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है और अब तक आईआईटी संघ द्वारा 36 विषयों पर एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की गई है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण योजना मंत्री उमा भारती ने लोकसभा में प्रश्नकाल के यह जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी संघ द्वारा दिसंबर 2014 के तुरंत बाद योजना का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया जाना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गंगा नदी की सफाई की रणनीति देने के लिए कहा है। गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए कुछ देशों से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव मिलने की जानकारी देते हुए उमा

भारती ने बताया कि कई देशों ने गंगा संरक्षण में हिस्सा लेने में रुचि दिखाई है। इसके अतिरिक्त 4969 करोड़ रुपए की लागत से जेआईसीए सहायता प्राप्त वर्तमान परियोजना के साथ-साथ जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) के साथ मिलकर काम करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी की जीवंतता एवं भव्यता को फिर से स्थापित करने के लिए अद्वितीयता, निर्मलता और नदी तट की सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण, जलीय जीवन की सुरक्षा और वनारोपण सुनिश्चित करके गंगा की समग्रता को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य बिंदुओं की पहचान की गई है।

# रायपुर: वहां खुल रहा अस्थायी आईआईटी, जहां आईआईटी खड़गपुर हो चुका है फेल

■ भिलाई के आईआईटी का उसी भवन में अस्थायी संचालन करने की तैयारी

**भिलाई (ब्यूरो)।** भिलाई के लिए निर्धारित आईआईटी (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) का अस्थायी संचालन रायपुर में जिस स्थान से किए जाने का प्रस्ताव है, वहां पहले आईआईटी खड़गपुर का सेंटर असफल साबित हो चुका है। हालत यह है कि सेंटर खुले होने की जानकारी तक सरकार छात्रों तक नहीं पहुंचा सकी। नतीजतन पिछले दो साल में सेंटर में एक भी दाखिला नहीं हुआ। ऐसे में भिलाई के आईआईटी के अस्थायी संचालन को लेकर छात्रों में क्या इमेज बनेगी यह चिंता का विषय है।

आईआईटी खड़गपुर ने रायपुर के जीईसी (शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज) में सन्-2012 में विस्तार केंद्र खोला, जिसमें एमटेक के पांच ब्रांच की डिस्टेंस एजुकेशन के तहत पढ़ाई कराई जा रही थी। इसमें छात्रों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लास लगती थी। जीईसी के प्रशासनिक भवन में प्रथम तल पर संचालित इस विस्तार केंद्र में इस सत्र में शुरू से ही ताला लगा है, क्योंकि केंद्र में पिछले दो सत्रों से किसी भी स्टूडेंट का दाखिला नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आईआईटी खड़गपुर के विस्तार केंद्र के लिए शासन ने भवन उपलब्ध कराकर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली, पर इसके प्रचार-प्रसार पर गंभीरता नहीं दिखाई। नतीजतन प्रदेश में आईआईटी का विस्तार केंद्र होने के बाद भी छात्र इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब इसी जगह शासन ने भिलाई में निर्धारित आईआईटी का अगले सत्र से अस्थायी संचालन जीईसी के इसी भवन से करने की योजना लोगों की समझ से परे है।



फाइल फोटो

## पता नहीं क्यों बंद कर दिया

1. आईआईटी खड़गपुर के विस्तार केंद्र में ताला क्यों लगा है ?

जब मैं कर्डिनेटर था, तब विस्तार केंद्र जीईसी भवन में संचालित था, कक्षाएं भी चल रही थी, अब मैं वहां नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ताला क्यों लगा है

2. लेकिन आप तकनीकी शिक्षा संचालनालय में प्रमुख पद पर हैं, ऐसे में आपको जानकारी तो होगी कि केंद्र में ताला लगा है ?

पहले साल तो दाखिले हुए थे, वर्तमान जानकारी मुझे नहीं है, आप वहां के प्राचार्य से बात कर लें, वह ही बेहतर बता पाएंगे।

-डॉ. जीएस बेदी,  
एक्स कर्डिनेटर आईआईटी

## कोई अधिकारी नहीं आया

1. आईआईटी खड़गपुर के विस्तार केंद्र में ताला क्यों लगा है ?

जानकारी नहीं है क्योंकि करीब छह महीने से यहां प्रभारी प्राचार्य हूँ, तब से ही केंद्र में ताला लगा है, इस बीच आईआईटी से किसी ने संपर्क भी नहीं किया।

2. आप तो पहले भी कॉलेज में प्राचार्य रह चुके हैं, व वहाँ के शिक्षक हैं ?

इससे पहले जब मैं था, तब केंद्र संचालित हो रहा था, फिर करीब एक साल मैं सीएसवीटीयू में पदस्थ था। इस बीच क्या हुआ पता नहीं।

-जीआर साहू  
जीईसी रायपुर

## 18-18 सीट थी आवंटित

आईआईटी खड़गपुर के रायपुर विस्तार केंद्र में एमटेक के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर साइंस ब्रांच के संचालन की अनुमति थी। इसमें हर ब्रांच में 18-18 सीटें हैं। केंद्र के संचालन के लिए जीईसी रायपुर ने दो कमरे आईआईटी खड़गपुर को उपलब्ध कराया है।

Navbharat Times ND 12/12/2014 P-14

# प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की पढ़ाई के लिए नए IIT!

■ ऋतिका चोपड़ा, नई दिल्ली  
स्मृति इरानी की कमान वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय IIT और IIM की तर्ज पर देश में भारतीय विद्या संस्थान यानी इंस्टिट्यूट ऑफ इंडोलॉजी शुरू करने की योजना बना रहा है। इनके जरिए मंत्रालय प्राचीन भारत के ज्ञान-विज्ञान पर रिसर्च को बढ़ावा देगा। इन संस्थानों के लिए वित्तीय मदद केंद्र सरकार देगी। मोटे तौर पर प्राचीन भारतीय भाषाओं, साहित्य और दर्शन की स्टडी को इंडोलॉजी कहा जाता है। सूत्रों की मानें तो इस कदम का मकसद वर्तमान स्कूली सिस्टम की खामियों को दूर करना है। आज कई ऐसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे, जिन्हें राजनीति और प्रशासन की प्राचीन बातों की मामूली जानकारी ही होगी या किसी साइंस ग्रेजुएट को पिछली तीन

सहस्राब्दियों का ज्ञान नहीं होगा। वहीं, एग्रिकल्चर साइंस में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट को देश में खेती-बाड़ी की परंपरा का पता नहीं होता है।

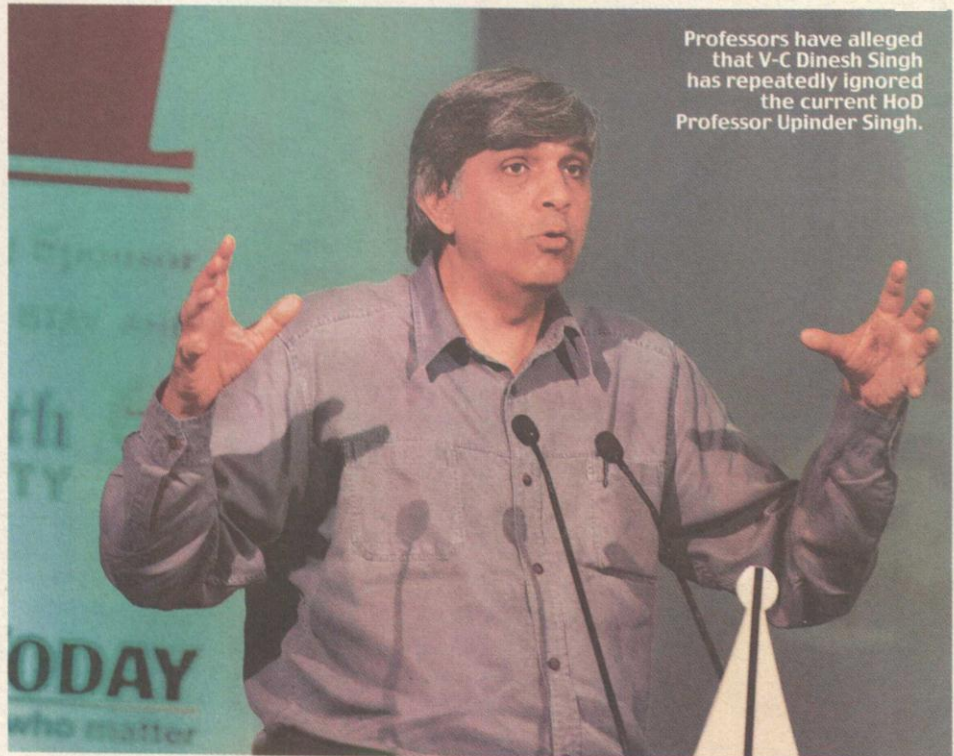
इंस्टिट्यूट ऑफ इंडोलॉजी पीजी डिप्लोमा, एमएस जैसे पीजी कोर्स और पीएचडी कराएंगे। इनके दायरे में प्राचीन भाषाओं और साहित्य के अलावा प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था और कारोबार, प्रशासन के तौर-तरीकों, पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, तकनीक, परंपरागत खेती-बाड़ी, जल प्रबंधन जैसे विषय आएंगे। सूत्र के मुताबिक, आगे चलकर ये संस्थान ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। मंत्रालय ने इस बारे में कॉन्सेप्ट नोट बनाया है। प्रस्तावित संस्थानों के लिए यह फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मांग सकता है। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन IIT की तर्ज पर प्रक्रिया की तहत होगा।

By **Heena Kausar**  
In New Delhi

SEVEN senior professors of the Delhi University's History Department on Thursday have written a letter to the Vice-Chancellor Dinesh Singh expressing concerns over the appointments in History Departments across many colleges and alleged that the ongoing process of appointments are being manipulated with vested interests.

The professors have alleged that the V-C has repeatedly ignored the current Head of the Department (HoD) Professor Upinder Singh. The letter states that the presence of HoD in the Selection Committee is a norm. "We find it strange that the present HoD is being consistently ignored... We do hope this is not because the university treats her as being someone who is unlikely to make appointments in a plicant way," the letter dated 8 December 2014, a copy of which is with MAIL TODAY, said.

The HoD said she doesn't know why she has been kept out of the selection panel.



Professors have alleged that V-C Dinesh Singh has repeatedly ignored the current HoD Professor Upinder Singh.

# DU teachers allege anomaly in selection

"Having the HOD in the panel has been the norm. But I don't know why I have not been included in the panel. This can be answered only by the authorities," Singh said.

The professors have said that the panel on the basis of which the subject experts from the designated Professors in the Department are created has a six month constitution. "At the end of every six months, new professors should be inducted into this panel. The same panel of three Professors has selected candidates since May 2014 and it seems that they are in the panels for other colleges for future appointments as well," the letter said.

The letter also raises the issue that all three professors of the selection committee have their specialisation in Ancient History while sound academic practice demands that subject-experts should be chosen from different areas of specialisation, like Ancient, Medieval, Modern

Indian, European and American History. "Best practice demands that the members of the selection committee should also represent different streams and that is why Professors with differing specializations were always included in the selection committees in the past. Colleges also followed this procedure in the past when they invited subject experts to the selection committee. We fail to understand why this is not being adhered to now," the letter, signed by prominent historians like Nayanjot Lahiri and Amar Farooqui, said.

Reacting to this letter, the Delhi University Teachers' Association President Nandita Narain said the process of appointments in the University is being manipulated in various ways.

"Such a letter corroborates the DUTA's position that the ongoing process of appointments is being subjected to several kinds of manipulations," Narain said.

The letter also raises the issue that all three professors of the selection committee have their specialisation in Ancient History

## THE GROUSES

“We find it strange that the present HoD is being consistently ignored. Considering that the University vests very critical administrative functions and responsibilities in the HoD, on what basis has she been kept out of the panel.”

Considering her academic stature, her publications and the fact she is the recipient of various awards, it is unlikely that it is her qualifications which the University has found lacking.

— Excerpts from the letter to the V-C

Times Of India ND 12/12/2014 P-11

# Times Group to set up Bennett Univ in G Noida

## To Start With Courses In Engg, Management, Entrepreneurship, Liberal Arts And Media

TIMES NEWS NETWORK

**Lucknow:** The Times Group on Thursday announced the setting up of the multi-faculty Bennett University in Greater Noida in Uttar Pradesh. To begin operations from July 2016, the university will come up on 68 acres of land, and to begin with, will offer courses in engineering, management, entrepreneurship, liberal arts and media. The university derives its name from Bennett, Coleman & Co Ltd (BCCL), the holding company for The Times Group.

Receiving the letter of allotment of land from UP chief minister Akhilesh Yadav, Times Group managing director Vineet Jain said, "Bennett University will be a world-class university in which we will invest Rs 600 crore. We are going to invite many international universities and institutions to partner with us." Jain thanked the chief minister and the government of UP for facilitating the allotment of land for the university in a short period of time.

Welcoming The Times Group's venture in UP, Akhilesh Yadav said, "I would like to thank Vineet Jain and The Times Group for choos-



Times Group MD Vineet Jain with UP chief minister Akhilesh Yadav at a function in Lucknow on Thursday to announce the setting up of the university

ing to invest in UP. I also urge the group to build this university soon. Such a big group setting up an educational institute will not only prevent brain drain from UP, but will also be able to attract more students from across India and abroad to UP."

Shrijeet Mishra, chief operating officer of BCCL and CEO of its education business, said, "Our aim is to create the best university in the world. At full capacity, Bennett University will accommodate 10,000 students. Our focus will be on building talent, and giving students

plenty of industry exposure and practical experience. We will bring in excellent quality education through our partnerships with global universities. This will not only be good for India, but also good for the world."

Mishra said Bennett University was already in talks with various global universities and institutes for partnerships. "We will have more clarity on who we tie up with by April 2015. For the engineering program, however, we already have an agreement with the renowned Georgia Institute of Technology."



# Apollo's Medvarsity ties up with Australian varsity for e-learning

## OUR BUREAU

Hyderabad, December 11

Medvarsity, a first medical e-learning initiative from Apollo group of hospitals, will work with the University of New South Wales (Australia) to collaborate in the healthcare e-learning space with a focus on the management of infectious diseases.

Addressing a press conference here on Thursday, Hariprasad, Chief Executive Officer of Apollo Central India, said that there was a severe scarcity for specialists who can deal with infectious diseases. "There is no structured curriculum for Infection Medicine in the country," he said.

## Course launch

Medvarsity will launch its maiden course, focusing on infectious diseases, next month. Targeted towards the doctors and other stakeholders who want to update their knowledge on the subject, the course material has been de-

veloped by leading medical practitioners from Apollo and UNSW's School of Public Health and Community Medicine.

"This programme is a blend of online and hands on training at Apollo Hospitals initially. There are a few other programmes in the pipeline through this collaboration," he said.

## Key aspects

The one year diploma course covers vaccines, current challenges in controlling the diseases, surveillance of infectious diseases and pharmacological and non-pharmacological interventions.

"India is facing challenges in facing emerging and endemic infectious diseases. There is a need to increase the number of trained personnel to address this issue," Raina McIntyre, Head of School of Public Health, UNSW, said here on Thursday as the two institutions joined hands.

Apollo Hospitals group Joint



Peter Smith (second left), Dean of University of New South Wales, Raina McIntyre, Head of School of Public Health, UNSW with K Hariprasad (right), CEO (Central), Apollo Hospitals and Kylie Bell (in red), Trade and Investment Commissioner (South Asia), Australian Trade Commission at the formation of the e-learning initiative in Hyderabad PV SIVAKUMAR

Managing Director Sangita Reddy said the threat of infectious diseases assuming alarming levels in the world. "The Medvarsity tie up with the Australian university would help develop a solu-

tion to address the challenge posed by infectious diseases.

"The collaboration between the two institutions would continue in other areas as well in future."

## IIT-M launches Biotechnology Incubator

The incubator to support four start ups to set up their business in the initial phase

BS Reporter | Chennai

December 11, 2014 Last Updated at 19:20 IST

The Indian Institute of Technology, Madras (IIT-M) has launched a [Biotechnology Incubator](#) to support the biotechnology start-ups to start their business and grow to a higher level.

The Incubation Cell of [IIT-M](#) is currently incubating 30 start ups a year and with the launch of the Incubator and one more incubator to join soon, this is expected to go up to 50 companies a year, said Ashok Jhunjhunwala, faculty-in-charge, IIT-M Research Park and Co-Chairman of IIT-M Incubation Cell.

The Biotech incubator is aimed at helping start-ups and [SMEs](#) develop globally competitive products and launch them into the market successfully, said the institution. The biotech start ups require a longer time to break even, at least 10 years, compared to an IT start up which might break even in 3-4 years, said Srikumar Suryanarayanan, CEO, Sea6 Energy, an expert in Biotech sector in the country.

The start ups in the sector would also require costly equipments compared to other start up businesses, to take up their projects properly, he added. The Biotechnology Industry Research Assistance Council, a public sector enterprise, is currently offering support to start ups and SMEs in the sector and currently support 120-130 companies including over 100 entrepreneurial ideas.

Four start ups - [Purius Nanosystems](#) Pvt Ltd which is working on point-of-care testing devices for single tests for [Tuberculosis](#) Bacilli, Malaria, [Hepatitis B](#) Virus or panel tests for HIV, FIB-Sol Life Technologies Pvt Ltd which develops low-cost bio fertilisers, Vital Bioscientific Solutions which develop model to simulate a system reaction to a drug and Yaathum Biotech which develops diagnostic test kits to identify full range of drug resistant TB strains in a single test - has been identified as the incubatees for the first phase.

## IIT-M launches Biotechnology Incubator

**The incubator to support four start ups to set up their business in the initial phase**

BS Reporter | Chennai

December 11, 2014 Last Updated at 19:20 IST

[http://www.business-standard.com/article/companies/iit-m-launches-biotechnology-incubator-114121101079\\_1.html](http://www.business-standard.com/article/companies/iit-m-launches-biotechnology-incubator-114121101079_1.html)

The Indian Institute of Technology, Madras (IIT-M) has launched a [Biotechnology Incubator](#) to support the biotechnology start-ups to start their business and grow to a higher level.

The Incubation Cell of [IIT-M](#) is currently incubating 30 start ups a year and with the launch of the Incubator and one more incubator to join soon, this is expected to go up to 50 companies a year, said Ashok Jhunjhunwala, faculty-in-charge, IIT-M Research Park and Co-Chairman of IIT-M Incubation Cell.

The Biotech incubator is aimed at helping start-ups and [SMEs](#) develop globally competitive products and launch them into the market successfully, said the institution. The biotech start ups require a longer time to break even, at least 10 years, compared to an IT start up which might break even in 3-4 years, said Srikumar Suryanarayanan, CEO, Sea6 Energy, an expert in Biotech sector in the country.

The start ups in the sector would also require costly equipments compared to other start up businesses, to take up their projects properly, he added. The Biotechnology Industry Research Assistance Council, a public sector enterprise, is currently offering support to start ups and SMEs in the sector and currently support 120-130 companies including over 100 entrepreneurial ideas.

Four start ups - [Purius Nanosystems](#) Pvt Ltd which is working on point-of-care testing devices for single tests for [Tuberculosis](#) Bacilli, Malaria, [Hepatitis B](#) Virus or panel tests for HIV, FIB-Sol Life Technologies Pvt Ltd which develops low-cost bio fertilisers, Vital Bioscientific Solutions which develop model to simulate a system reaction to a drug and Yaathum Biotech which develops diagnostic test kits to identify full range of drug resistant TB strains in a single test - has been identified as the incubatees for the first phase.

## DU to soon get new marks and evaluation system

<http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-university-du-marks-evaluation-system/1/406255.html>

Delhi University (DU) may soon see a change in the way students are marked and evaluated for their performance. The university has formed a seven-member committee to give suggestions for evolving a uniform policy for grading students after the University Grants Commission (UGC) issued a notification asking all universities to adopt the Choice Based Credit System (CBCS) from the next academic year.

A source said: "The committee will have a relook at the present system in DU and formulate suggestions in order to make the system in tune with the UGC guidelines. At present, every university is following its own system of evaluation and marking due to which some students are getting marks in grades while some are getting in per cent. We need to evolve a uniform policy for results."

Maharaja Agrasen College Principal Sunil Sondhi will head the committee. DU's Joint registrar Ram Dutt, Sri Venkateswara College Principal Hemlata Reddy, Aryabhata College Principal **Manoj Sinha**, Shivaji College's senior Associate Professor Virendra Bhardwaj, Deen Dyal Upadhyay's senior teacher Manoj Saxena and senior Associate Professor at Dyal Singh College Ajay Bhagi are the panel members, the source said.

According to UGC, the new system will ensure seamless mobility of students across higher educational institutions in the country and abroad. "The credit earned by a student can be transferred and would be of help to them in the event of their seeking migration from one institution to another," UGC had said in the notification.

The source said: "If someone wants to compare these grades while a student migrates from one university to another, then it becomes very difficult. UGC wants a uniform system which will enable migration from one college to another and migration from one university to another easier."

However, the teaching community has expressed apprehensions over appointment of such a committee and said that any change in the academic structure and evaluation needs to be ratified by the Academic Council (AC) and the Executive Council (EC). A teacher said: "A committee cannot just make changes." But, the committee members explained that they will only make suggestions.

Committee member Bhagi said: "We will prepare a paper based on the guidelines issues by the UGC for CBCS. The paper prepared by us shall be placed for consideration to the appropriate authorities which in the case of the university includes AC and EC. There would be consultations with staff associations as well for further suggestions and improvements."

According to the UGC, under CBCS, students can take courses of their choice, learn at their own pace, undergo additional courses, acquire more than the required credits and adopt an interdisciplinary approach to learning. The courses will be of three types -core, elective and foundation.